

भारत सरकार  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5631

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए  
वैज्ञानिक अनुसंधान

5631. श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता के संदर्भ में विश्व में भारत की स्थिति की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता के संदर्भ में भारत की स्थिति में सुधार हो रहा है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
- (घ) वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में देश की स्थिति में सुधार हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (ग): स्कोपस (एल्सवीयर) डाटाबेस पर आधारित डीएसटी संचालित अध्ययन 2019 के अनुसार, वैज्ञानिक प्रकाशनों के उल्लेखों की संख्या की दृष्टि से वैज्ञानिक अनुसंधान की मूल्यांकित गुणवत्ता में भारत 2017 के दौरान 10 वें स्थान पर था। वैज्ञानिक प्रकाशनों के उल्लेखों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान लगातार सुधार रहा है और इससे भारत 2011 में 14 वें स्थान से ऊपर होकर 2017 में 10 वें स्थान पर पहुँच गया है।

(घ) वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में देश की स्थिति में सुधार करने के लिए, सरकार ने वैज्ञानिक विभागों के लिए योजनागत आवंटनों में उत्तरोत्तर वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, अकादमिक और राष्ट्रीय संस्थानों में एस एण्ड टी के उभरते हुए और अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों और सुविधाओं के सृजन जैसे अनेक कदम उठाए हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना संवर्धन निधि (फिस्ट); अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा केन्द्र (सैफ), अनिवासी भारतीयों (एनआरआईएस) और विदेशी भारतीय नागरिकों (ओसीआईएस) सहित प्रतिष्ठित विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए आगंतुक उन्नत संयुक्त अनुसंधान (वज्र) संकाय स्कीम, विदेशी आगंतुक डाक्टरल अध्येतावृत्ति (ओवीडीएफ), प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति, शिक्षक अनुसंधान उत्कृष्टता सहायकवृत्ति (टीएआरई) और प्रतिष्ठित अन्वेषक पुरस्कार (डीआईए), डीबीटी-टीडब्ल्यूएस अंतरराष्ट्रीय अध्येतावृत्ति जैसी स्कीमें प्रारंभ की हैं और सरकार बहिष्कार अनुसंधान निधीयन आदि के माध्यम से वैज्ञानिकों के लिए पर्याप्त अनुदान प्रदान कर रही है।

\*\*\*\*\*